ई संदेश

04जून, 2026 | अंक - 208

सात दिन, सात पृष्ठ

- सुशासन और सुरक्षा से सशक्त होता उत्तर प्रदेश, मऊ को मिली ₹392 करोड़ से अधिक की विकास सौगात
- गांव ही देश के स्वावलंबन का वास्तविक आधार: मुख्यमंत्री
- राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बना उत्तर प्रदेश, लखनऊ में भव्य नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण
- बिजनौर में विस्थापित परिवारों को मिला भूमि का मालिकाना अधिकार
- प्रदेश के मेधावियों को मिला सम्मान : मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र-छात्राओं को किया पुरस्कृत
- विकास के और ऊँचे हुए प्रतिमान : कुशीनगर में ₹424 करोड़ की विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास
- गोरखपुर में जनता को समर्पित हुआ सौन्दर्यीकृत चिलुआताल
- मुख्यमंत्री ने खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में कृषि विकास और फसल विविधीकरण पर दिया जोर
- मुख्यमंत्री जी ने कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती परीक्षा और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर दिए कड़े निर्देश
- मुख्यमंत्री जी ने गीडा में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 03 जून, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

सुशासन और सुरक्षा से सशक्त होता उत्तर प्रदेश, मऊ को मिली ₹392 करोड़ से अधिक की विकास सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 29 मई, 2026 को जनपद मऊ में 392 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, प्रतीकात्मक चेक, लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित किए। साथ ही, उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिना भेदभाव के किया जाने वाला विकास ही आमजन के जीवन स्तर को उठाने का वास्तविक माध्यम बनता है। सड़क, पुल, स्वास्थ्य केंद्र या बाढ़ सुरक्षा के कार्य किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुविधा और सुरक्षा के लिए निर्मित होते हैं। उन्होंने अच्छे जनप्रतिनिधियों और लोक-हितैषी सरकार के गठन को इस निरंतर प्रगति का मुख्य आधार बताया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदलते भारत की भव्य तस्वीर को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में केवल चार प्रमुख जातियां—गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता किसान हैं, जिनके सर्वांगीण उत्थान से ही भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनेगा। इस दौरान उन्होंने मऊ की महान विभूतियों को याद किया और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं में सड़क, सेतु, ग्रामीण पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और पुलिस विभाग की आवासीय व अनावासीय सुविधाएं शामिल रहीं। गरीब परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और तकनीकी विकास के लिए राजकीय आईटीआई व पॉलीटेक्निक जैसी महत्वपूर्ण सौगातें जनपद को प्राप्त हुईं।

लोक कल्याण की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। संकट की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से पीड़ित किसान परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाई जाने की बात कही। उन्होंने मऊ में पीपीपी मॉडल पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के जल्द उद्घाटन होने की जानकारी भी साझा की।

विशेष निर्देशों और व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने घोसी चीनी मिल के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों के हित में समय पर धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही, उन्होंने आम जनता को बदलते मौसम के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा ताकि लोग भीषण धूप, लू और गर्मी से सुरक्षित रहें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे आकाशीय बिजली और आंधी-तूफान के समय खुले में या पेड़ों के नीचे जाने से बचें और केवल पक्के तथा सुरक्षित स्थानों पर ही शरण लें।

वर्ष 2017 से पूर्व की अराजक स्थितियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े रहे। माफिया तत्वों के आगे नतमस्तक तत्कालीन व्यवस्था के कारण धार्मिक आयोजनों में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी। कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होने से अब प्रदेश में भयमुक्त और सुरक्षित माहौल स्थापित हुआ, जिससे युवाओं के समक्ष आया पहचान का संकट भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया।

गांव ही देश के स्वावलंबन का वास्तविक आधार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 29 मई, 2026 को जनपद मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के उपरान्त आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने चिकित्सालय के विभिन्न वॉर्डों और तकनीकी इकाइयों का गहन निरीक्षण कर वहां उपलब्ध जीवनरक्षक उपकरणों की कार्यप्रणाली की बारीकी से जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ0 पी0एन0 सिंह की दिवंगत पत्नी श्रीमती सुषमा सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि गांव ही देश के स्वावलम्बन के वास्तविक आधार स्तंभ बने और गांवों के आत्मनिर्भर होने से ही देश आत्मनिर्भरता की सुदृढ़ इकाई के रूप में स्थापित हो सका। उन्होंने ताजोपुर गांव में निर्मित हॉस्पिटल, सैनिक पब्लिक स्कूल, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा आई0टी0आई0 को केवल एक संस्थान न मानकर प्रदेश के लिए एक बड़ा निवेश बताया, जिसने स्थानीय स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखी और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए।

डबल इंजन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मऊ जनपद की रोड और रेल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार हुआ, जिससे मऊ से लखनऊ की दूरी घटकर मात्र 03 घण्टे तथा वाराणसी व गोरखपुर की दूरी क्रमशः डेढ़ और एक घण्टे रह गई। इसके अलावा प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन, 65 लाख गरीबों को आवास, 01 करोड़ 06 लाख परिवारों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ तथा प्रत्येक गरीब के घर तक उज्ज्वला योजना का निःशुल्क गैस कनेक्शन पहुंचाया गया। सुरक्षा के मोर्चे पर अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति से प्रदेश में एक भयमुक्त माहौल बना, जिसने युवाओं के सामने से पहचान का संकट सदैव के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 41 मेडिकल कॉलेज बन पाए, जिनकी संख्या अब बढ़कर 83 तक पहुंच गई।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने देश और प्रदेश की उन्नति के लिए कुछ विशेष निर्देश और आह्वान किए। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को 'पंचप्रण' के संकल्प से जुड़ने का कड़ा निर्देश दिया, जिसके तहत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना और गुलामी की हर सोच से पूरी तरह मुक्त होना अनिवार्य माना गया। उन्होंने देश को विभाजित करने वाली जातिवाद, छुआछूत, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसी कुप्रथाओं की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने इनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त किए बिना देश का वास्तविक विकास संभव नहीं हो सकता, इसलिए 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए सामाजिक समरसता अपनाना अत्यंत आवश्यक माना गया है।

मुख्यमंत्री जी ने नागरिक कर्तव्यों के पालन पर विशेष बल देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से समझने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में डटे रहने वाले सैनिकों और आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखने का निर्देश दिया। उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्शों का स्मरण कराते हुए जननी और जन्मभूमि की सेवा को स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर बताया। उन्होंने शिक्षित समाज को डॉ. पी.एन. सिंह के इस सराहनीय प्रयास से प्रेरणा लेकर अपनी मातृभूमि के ऋण से उऋण होने के लिए रचनात्मक कार्यों में निरंतर योगदान देने की पुरजोर अपील की।

राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बना उत्तर प्रदेश
लखनऊ में भव्य नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 मई, 2026 को संयुक्त रूप से जल सीमाओं के सजग प्रहरियों की वीरता, अदम्य साहस एवं आधुनिक तकनीकी दक्षता को समर्पित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लखनऊ में 19 करोड़ रुपये की लागत से दो एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित यह शौर्य वाटिका नौसेना शौर्य संग्रहालय के द्वितीय चरण का हिस्सा बनी। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से प्रदेश की राजधानी को राष्ट्रभक्ति, सैन्य गौरव और पर्यटन का एक नया उत्कृष्ट केंद्र प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए रक्षा मंत्री जी ने इस क्षण को अत्यंत गौरवशाली बताते हुए कहा कि यह वाटिका आने वाले समय में लखनऊ की नई पहचान बनी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सुदृढ़ नेतृत्व में तेजी से विकास पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश की सराहना की। रक्षा मंत्री जी ने रेखांकित किया कि पूर्ववर्ती काल में जिस प्रदेश की पहचान अराजकता, गुंडाराज और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' के रूप में स्थापित रही, वह वर्तमान में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' और बेहतरीन कानून-व्यवस्था के लिए जाना गया। बेहतर सुरक्षा माहौल के कारण ही बड़े निवेशक अब प्रदेश में निवेश करने के लिए पूरी तरह तत्पर दिखाई दिए।

रक्षा मंत्री जी ने शौर्य वाटिका के लिए प्राइम लोकेशन पर त्वरित भूमि उपलब्ध करानेऔर रिकॉर्ड समय में कार्य पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को सराहा। उन्होंने भारतीय नौसेना के महत्व और लखनऊ के ऐतिहासिक संबंध पर प्रकाश डालते हुए आई0एन0एस0 गोमती का विशेष उल्लेख किया। वर्ष 1988 में नौसेना में शामिल हुए इस युद्धपोत के आधिकारिक चिन्ह (क्रेस्ट) पर लखनऊ का ऐतिहासिक छतर मंजिल अंकित रहा, जिसने हिंद महासागर में इस शहर का गौरव बढ़ाया। वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त होने के बाद इस वास्तविक युद्धपोत की मिसाइलें, टारपीडो ट्यूब, रडार, मुख्य तोप, सर्विलांस एयरक्राफ्ट और मल्टीरोल हेलीकॉप्टर अब इस वाटिका में जीवंत प्रेरणा के रूप में स्थापित किए गए। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विज़न का उल्लेख करते हुए देश के बढ़ते रक्षा उत्पादन और निर्यात के आंकड़े भी साझा किए।

समारोह में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना के पराक्रम तथा हमारे सैनिकों की विषम कार्यपरिस्थितियों से परिचित कराने में यह वाटिका एक ऐतिहासिक माध्यम सिद्ध हुई। उन्होंने नौसेना की विराट सोच का संदर्भ देते हुए कहा कि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोच भी विराट होनी आवश्यक रही। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए विकसित भारत के 'पंचप्रण' की चर्चा करते हुए उन्होंने वर्दीधारी बलों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखने को देश के सकारात्मक विकास की अनिवार्य शर्त बताया।

इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने युवा पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करने तथा उन्हें सेना के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण चौराहों पर सेना के सेवानिवृत्त टैंक स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें देखकर युवाओं के मन में भारतीय सेना में शामिल होने और देश की सेवा करने का नया भाव उत्पन्न हो। इसके साथ ही उन्होंने नौसेना शौर्य संग्रहालय के आगामी चरणों के कार्यों को भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ समय-सीमा के भीतर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में व्याप्त कर्फ्यू और दंगों के माहौल को पूरी तरह समाप्त कर सुदृढ़ सुरक्षा चक्र तैयार किया गया, जिससे विकास योजनाओं को प्रभावी गति मिली। उन्होंने भारतीय ऋषि परंपरा के संदेश 'अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च' का उल्लेख करते हुए दृढ़ता से कहा कि देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले दुश्मनों के खिलाफ सेना का पराक्रम ही हमारा परम धर्म रहा। उन्होंने 25 दिसम्बर, 2025 को उद्घाटित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' के बाद लखनऊ को मिले इस नए शौर्य केंद्र को राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने वाला अनुपम उपहार बताया।

बिजनौर में विस्थापित परिवारों को मिला भूमि का मालिकाना अधिकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 01 जून, 2026 को जनपद बिजनौर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पाकिस्तान से विस्थापित 1,635 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों व लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र प्रदान कर उनके दशकों पुराने इंतजार को समाप्त किया। इस अवसर पर विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चेक वितरित किए गए। साथ ही ग्रामीण स्वावलम्बन को गति देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित 'विदुर प्रेरणा कैफे' का उद्घाटन भी संपन्न हुआ।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर को अत्यंत भावुक और आनंद का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष दर वर्ष और दशक दर दशक बीतने के बाद विस्थापित परिवारों की चौथी पीढ़ी को उनकी अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हुआ, जिससे लगभग 08 से 10 हजार की आबादी सीधे लाभान्वित हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाजन के समय धार्मिक कट्टरता के कारण पाकिस्तान से जबरन निकाले गए इन हिंदू और सिख परिवारों को बसाने तथा नागरिकता दिलाने का मार्ग नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के माध्यम से प्रशस्त हुआ।

महाभारत कालीन महात्मा विदुर की पावन धरा को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। उन्होंने बिजनौर को समृद्धशाली कारीगरों, ऊर्जावान युवाओं और प्रगतिशील किसानों की भूमि बताते हुए आश्वस्त किया कि यह क्षेत्र विकास के पैमाने पर कभी पीछे नहीं छूटेगा। बिजनौर में महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, शानदार हाईवे का निर्माण और नई रेलवे सुविधाओं के नेटवर्क का विकास संपन्न हुआ, जिसके साथ ही इस जनपद को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की महत्वपूर्ण तैयारी को आगे बढ़ाया गया। पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह की स्मृतियों को जीवित रखते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को उन्नत तकनीक और डिजाइन की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई।

पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक पर्व और त्योहार मनाना भी एक सपना बन चुका था तथा बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा सदैव खतरे में रही। वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद और कट-सिफारिश की संस्कृति पूरी तरह समाप्त हुई और बिजनौर के युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ पुलिस बल व अन्य सेवाओं में नियुक्तियां प्राप्त हुईं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे डिप्टी एस0पी0 और अन्य उच्च पदों पर नियुक्त कर सम्मानित किया गया। किसानों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम के मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि और औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य को यादगार बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इसी श्रृंखला में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल हाथ में लेने का कड़ा निर्देश दिया। बिजनौर में व्यापारिक सुगमता बढ़ाने के लिए मण्डी हेतु आरक्षित की गई भूमि पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आवश्यक धनराशि निर्गत करने की बात कही।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रविरोधी, गरीब-विरोधी और समाज को विभाजित करने वाली ताकतों के खिलाफ अत्यंत कठोर रुख अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के खिलाफ द्रोह करने वाले तत्वों के प्रति पूरी निर्ममता और कठोरता से निपटा जाए। मानवता की रक्षा के लिए सज्जनों के प्रति उदारता और दुष्टों के दमन के लिए हर स्तर पर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सांस्कृतिक संस्कारों को अक्षुण्ण रखने की दिशा में गौमाता और मां गंगा के संरक्षण व सम्मान को प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में रेखांकित किया।

प्रदेश के मेधावियों को मिला सम्मान : मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र-छात्राओं को किया पुरस्कृत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 01 जून, 2026 को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित 'मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह' में विभिन्न बोर्डों की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। इस भव्य समारोह में राज्य स्तरीय मेधावियों को 01 लाख रुपये का प्रतीकात्मक चेक, टैबलेट, साफा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आधारित एक ज्ञानवर्धक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी संपन्न हुआ।

प्रदेश भर में एक साथ कुल 1,682 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का यह वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्य समारोह में विभिन्न शिक्षा बोर्डों के शीर्ष 10 स्थानों पर रहे 223 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इन मेधावियों में छात्राओं की संख्या 138 और छात्रों की संख्या 85 रही, जो महिला सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर को स्पष्ट रूप से दर्शाती दिखी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में भी बालिकाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र और समाज की प्रगति का सबसे सशक्त आधार माना गया।

शिक्षा व्यवस्था में पिछले नौ वर्षों के भीतर आए क्रांतिकारी बदलावों को रेखांकित करते हुए परीक्षाओं को पूरी तरह नकलविहीन, शुचितापूर्ण और पारदर्शी बनाया गया। पूर्ववर्ती काल की बदहाली और विलंब की संस्कृति को समाप्त कर अब लगभग 56 लाख विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं मात्र 14 से 15 दिनों में संपन्न कराकर उतने ही दिनों में परिणाम भी घोषित कर दिए गए। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से विद्यालयों का कायाकल्प कर वहां आधुनिक क्लासरूम, पेयजल और टॉयलेट की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही अटल टिंकरिंग लैब और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे नवाचारों से उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षण संस्थानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया गया।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने विद्यार्थियों से स्मार्टफोन के लिए माता-पिता पर अनावश्यक दबाव न बनाने तथा सोशल मीडिया पर न्यूनतम समय बिताने का कड़ा निर्देश दिया। बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए उन्हें डिजिटल लाइब्रेरी और समाचार पत्रों के नियमित अध्ययन से अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। छोटे बच्चों को स्मार्टफोन देने के घातक परिणामों के प्रति आगाह करते हुए अभिभावकों को बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की सख्त हिदायत दी गई। विद्यार्थियों को अति-आत्मविश्वास की भावना से सर्वथा दूर रहने और पाठ्यक्रम व जीवन की छोटी से छोटी बातों पर गंभीरता से ध्यान देने का निर्देश प्राप्त हुआ, क्योंकि अति-आत्मविश्वास को ही असफलता का सबसे बड़ा कारण माना गया।

शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के व्यावहारिक संचालन के संबंध में विशेष निर्देश देते हुए स्पष्ट किया गया कि परीक्षाएं विद्यार्थियों को मानसिक रूप से परेशान करने का जरिया नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम होनी चाहिए। परीक्षकों को अत्यंत जटिल प्रश्न पत्र बनाने की संकुचित प्रवृत्ति से दूर रहने तथा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप सुगम प्रश्न तैयार करने का कड़ा निर्देश दिया गया। युवाओं को ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग करने, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा समय पर सोने, जागने और भोजन करने की अनुशासित जीवनशैली अपनाने की सीख दी गई। अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा, संस्कृति, विरासत और परिवेश की व्यावहारिक जानकारी रखने तथा सफलता के लिए किसी भी शॉर्टकट को न अपनाकर केवल शुद्ध नीयत और अनवरत परिश्रम पर भरोसा करने का आह्वान किया गया।

विकास के और ऊँचे हुए प्रतिमान : कुशीनगर में ₹424 करोड़ की विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 जून, 2026 को जनपद कुशीनगर में 424 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस विशेष अवसर पर उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, प्रतीकात्मक चेक, चाभी और टूलकिट प्रदान कर लाभान्वित किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई भव्य विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कुशीनगर की प्रगति पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी संपन्न हुआ।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कुशीनगर को वैदिक एवं रामायण कालीन समृद्ध विरासत का साक्षी, महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली तथा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की पावन धरा बताया। उन्होंने इस भूमि का संबंध भगवान श्रीराम के पुत्र कुश से जोड़ते हुए यहां के ऊर्जावान युवाओं, समर्पित किसानों और अपनी पीढ़ियों को संस्कारित करने वाली माताओं-बहनों के योगदान को सराहा। उन्होंने रेखांकित किया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कुशीनगर अपनी विकास यात्रा को बुलेट स्पीड से आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहा।

सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि कुशीनगर जनपद में 90,000 गरीबों को आवास तथा 03 लाख 14 हजार से अधिक परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में जनपद को मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट जैसी बड़ी सुविधाएं मिल चुकी हैं और नए एयरक्राफ्ट आने के बाद यहाँ से वायु सेवा को और अधिक विस्तार दिया जाएगा। इसी शैक्षणिक सत्र से कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का संचालन प्रारंभ होने की घोषणा से क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य को नई मजबूती मिली। इसके साथ ही जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी को क्षेत्र से पूरी तरह समाप्त किया गया।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सख्त कानून और व्यवस्था का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षात्मक वातावरण के कारण अब कुशीनगर के युवा बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों, पुलिस भर्ती और निजी निवेश के माध्यम से गरिमापूर्ण रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के क्रम में सरकार ने फाजिलनगर का नाम बदलकर 'पावागढ़' करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 500 वर्षों के संघर्ष के उपरांत अयोध्या में निर्मित हुए भव्य श्रीराम मंदिर का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे त्रेतायुग की साक्षात अनुभूति बताया।

विकासपरक व्यवस्थाओं और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को गन्ने के मूल्य का 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ी हुई दर से समयबद्ध और त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक नए कोर्सेज शुरू करने और मेडिकल कॉलेज में स्थानीय युवाओं के प्रवेश को सुगम बनाने की हिदायत दी। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर यह संकल्प दोहराया कि विकास के लिए आवंटित होने वाली एक-एक पाई का कड़ाई से हिसाब रखा जाए, ताकि कोई भी भ्रष्ट तत्व शासकीय धन में सेंध न लगा सके। प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने और सुशासन व सुरक्षा के इस मजबूत चक्र को निरंतर गति देने का आह्वान भी किया गया।

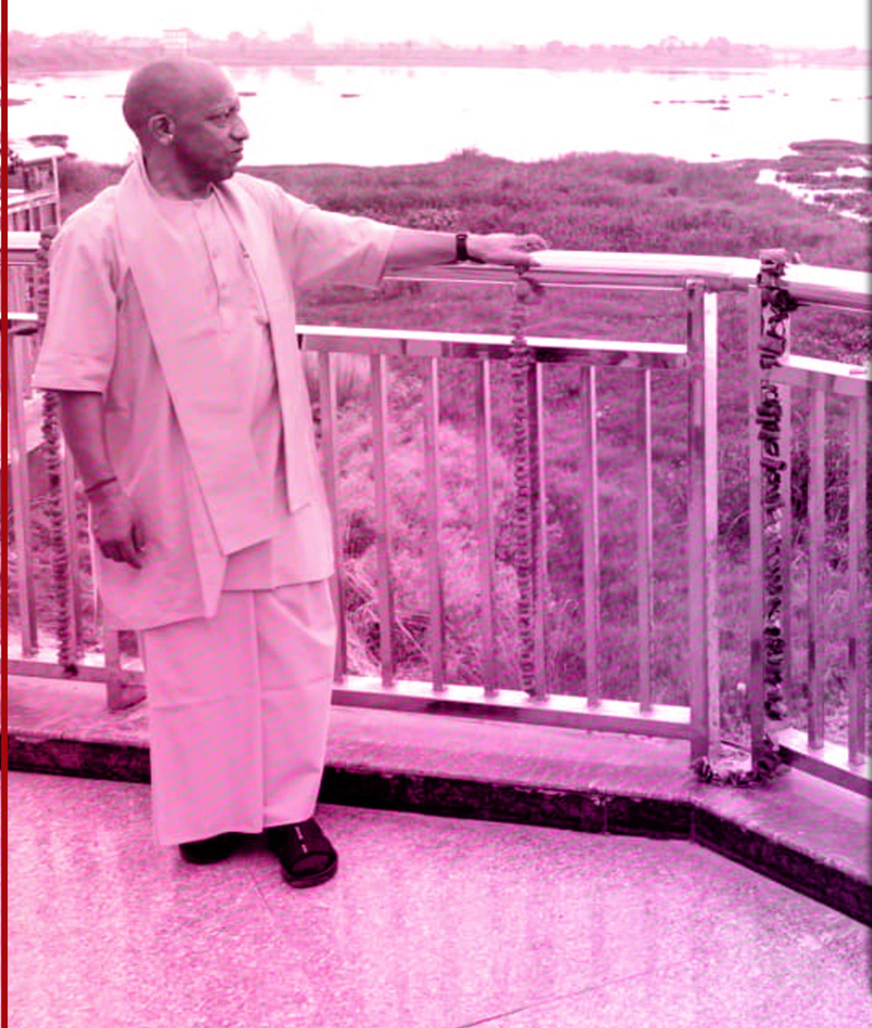

गोरखपुर में जनता को समर्पित हुआ सौन्दर्यीकृत चिलुआताल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 जून, 2026 को जनपद गोरखपुर में 20.35 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न चिलुआताल के पर्यटन विकास, सौन्दर्यीकरण एवं विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित भजन संध्या स्थल और सुसज्जित घाट का सघन निरीक्षण करने के साथ ही विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन और वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर के नागरिकों और आगंतुकों के लिए ईको-टूरिज्म एवं प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त एक नया दर्शनीय स्थल उपलब्ध हुआ। रामगढ़ताल के बाद चिलुआताल के इस पहले चरण के विकास से स्थानीय पर्यटन को सर्वथा नए आयाम मिले। जल निकायों पर होने वाले अवैध कब्जों और गंदगी के साम्राज्य को समाप्त कर डबल इंजन सरकार ने इन प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन का मार्ग प्रशस्त किया।

गोरखपुर की बदलती वैश्विक छवि की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब यह शहर केवल स्मार्ट सिटी नहीं, बल्कि 'सेफ सिटी' और 'सस्टेनेबल सिटी' के रूप में मजबूती से स्थापित हुआ। बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखाने के पुनर्संचालन, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जैसी बहुआयामी गतिविधियां क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार बनीं। पर्यावरण संरक्षण और 'नेट जीरो' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया के साथ मिलकर चिलुआताल में "20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट" स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया गया, जो कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की दिशा में बड़ा कदम बनी।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने चिलुआताल झील के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसके चारों ओर व्यापक स्तर पर वृहद वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य की कार्ययोजना तय करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिलुआताल को आगामी चरणों में रामगढ़ताल की तर्ज पर पूरी तरह विकसित कर एक बेहतरीन वॉटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित किया जाए।

शहरी स्वच्छता और नागरिक कर्तव्यों पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने महानगरवासियों और स्वयंसेवी संगठनों को पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक व गंदगी मुक्त स्वच्छ सिटी बनाने में सक्रिय योगदान देने का निर्देश दिया। उन्होंने 05 जून से 21 जून के मध्य आयोजित होने वाले विशेष अभियान के अंतर्गत 'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम को जन-आंदोलन बनाने की हिदायत दी, जिसके तहत वन विभाग, नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण को चिलुआताल व रामगढ़ताल के किनारों पर सघन पौधरोपण करने के निर्देश प्राप्त हुए। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के सुअवसर पर दोनों झीलों के सुरम्य तटों पर विशेष योग शिविरों के गरिमामय आयोजन हेतु भी अधिकारियों कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में कृषि विकास और फसल विविविधीकरण पर दिया जोर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 03 जून, 2026 को जनपद गोरखपुर में खरीफ अभियान 2026 के अन्तर्गत गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ मण्डलों की संयुक्त मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2026 का शुभारम्भ करने के बाद कृषि सुधारों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विगत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व सुधारों से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है और वे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। मानसून की चुनौतियों के बीच यह गोष्ठी किसानों को तकनीक, उन्नत बीज तथा फसल चक्र के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश की कृषि विकास दर 08 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 18 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। देश की केवल 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद उत्तर प्रदेश देश का 21 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित कर शीर्ष स्थान पर है। राज्य में फसल ऋण मोचन योजना, लागत का डेढ़ गुना दाम, 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा और निजी व सरकारी नलकूपों को निःशुल्क बिजली जैसी ऐतिहासिक सुविधाएं दी गईं, जिस पर सरकार प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपये का भार वहन कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने किसानों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' की सराहना की, जिसके तहत आपदा या हादसे का शिकार होने वाले किसानों व बंटाईदारों के परिवारों को 24 घंटे के भीतर 05 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। उन्होंने कृषि उत्पादन में तीन गुना अधिक वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए किसानों से बीज की गुणवत्ता, उन्नत तकनीक और फसल चक्र अपनाने की अपील की। इसके साथ ही लखनऊ में बन रहे चौधरी चरण सिंह सीड पार्क और कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से औद्यानिक फसलों, जैसे आम के निर्यात की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के लिए न्यूनतम केमिकल और पेस्टीसाइड का उपयोग कर प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती को कृषि लागत कम करने और गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का बेहतरीन माध्यम बताते हुए उन्होंने किसानों से मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुरूप फसल विविधीकरण और सह-फसली कृषि अपनाने का आह्वान किया। सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बिना कोई टैक्स बढ़ाए लगातार किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती परीक्षा और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर दिए कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 03 जून, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जनसहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस से अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को उन्होंने जनभागीदारी और जनजागरण का व्यापक अभियान बनाने को कहा।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अन्तर्गत न्यूनतम 05 करोड़ पौधों का रोपण किया जाए और पौधों की पर्याप्त उपलब्धता, जियो टैगिंग तथा उनके संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य करने तथा इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही। आगामी 05 से 21 जून तक की अवधि में प्रभारी मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में समाज के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, अभियंताओं, उद्योगपतियों, अधिवक्ताओं, युवा उद्यमियों तथा स्टार्टअप इनोवेटरों के साथ संवाद स्थापित करने पर बल दिया।

आगामी 08, 09 एवं 10 जून को दो पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न होने पाए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की सहभागिता को देखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप यातायात प्रबन्धन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सभी परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं केन्द्र व्यवस्थापक पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आगामी 06 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाने अथवा भ्रामक एवं असत्य सूचनाएं प्रसारित करने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की सतत् और गहन निगरानी की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एक भी अभ्यर्थी को धूप में खड़ा न रहना पड़े तथा परीक्षा केन्द्रों पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराये पर अन्तर्जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए तथा सभी परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ व्यवस्थाओं की निगरानी करने तथा अभ्यर्थियों को सुगम, सुरक्षित एवं सकारात्मक परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी।

मुख्यमंत्री जी ने गीडा में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 03 जून, 2026 को जनपद गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में 208 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स एवं ई0डब्ल्यू0एस0-एल0आई0जी0 आवासीय परिसर सहित 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार शुरू हो रहा यह फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स युवा उद्यमियों के लिए एम0एस0एम0ई0 से जुड़े नए उद्योगों की स्थापना हेतु रेडी-टू-यूज और प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर कार्य करेगा। इस अभिनव प्रयास के माध्यम से कम पूंजी में रेडीमेड गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे 100 से अधिक उद्योग एक ही कैंपस में संचालित हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 09 वर्षों में गीडा क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं और यहां बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं। 7000 एकड़ में धुरियापार क्षेत्र के विस्तार के साथ ही वहां सीमेंट, पेंट और सी0एन0जी0 निर्माण के उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को सुशासन व समृद्धि का आधार बताते हुए कहा कि वर्ष 2017 से अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही उत्तर प्रदेश आज सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल बना है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के कल्याण की चर्चा करते हुए कहा कि गीडा द्वारा फैक्ट्रियों के नजदीक ही कार्मिकों के रहने के लिए सस्ती दरों पर ई0डब्ल्यू0एस0 आवास की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे लगभग 100 श्रमिक परिवारों को आश्रय मिलेगा। उन्होंने एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण से स्थानीय स्तर पर लगभग 03 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने और भ्रष्टाचार पर कठोरता से लगाम कसकर प्रदेश के 09 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की बात कही। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार द्वारा विरासत के संरक्षण के साथ विकास की इस प्रक्रिया को अनवरत जारी रखने का संकल्प दोहराया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने ई0डब्ल्यू0एस0-एल0आई0जी0 आवास एवं औद्योगिक भूखंड के आवंटियों को आवंटन पत्र तथा नाईलेट (एन0आई0ई0एल0आई0टी0) कौशल केंद्र से प्रशिक्षित छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व बच्चों का अन्नप्राशन कराने के साथ ही परिसर में पौधरोपण भी किया। उन्होंने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 03 जून, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

» मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 (रबी फसल) में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मोटे अनाज मक्का क्रय नीति का निर्धारण किया है। नीति में मोटे अनाज के अन्तर्गत मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मक्का क्रय की अवधि 15 जून, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक होगी। मक्के की खरीद जनपद फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बदायूँ, शाहजहाँपुर, रामपुर, सम्भल, बुलन्दशहर, हापुड़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गोण्डा, फतेहपुर एवं मिर्जापुर में की जाएगी। अन्य जनपदों में आवक के दृष्टिगत खाद्य आयुक्त द्वारा मक्का खरीद का निर्णय लिया जा सकेगा।

» मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 18 शहरों एवं उनके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में नगरीय बस सेवाओं के लिए ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जी0सी0सी0) मॉडल पर ई-बसों को संचालित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह ई-बसें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, वाराणसी एवं नोएडा (जेवर) सहित संचालित की जाएंगी।

» मंत्रिपरिषद ने राज्य विधि अधिकारीगण को दी जाने वाली रिटेनरशिप/प्रति सुनवाई फीस में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों के विनियमितीकरण तथा विकास क्षेत्र/विस्तारित विकास क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र, जिनकी महायोजना तैयार नहीं है, में मानचित्र स्वीकृति हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आगरा, बरेली तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरणों हेतु सीड कैपिटल की अधिकतम धनराशि 355.06 करोड़ रुपये अनुमन्य करते हुए प्रथम किश्त के रूप में कुल 225 करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए यह धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

» मंत्रिपरिषद ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय पाण्डुनगर, कानपुर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा संचालित जाजमऊ चिकित्सालय, कानपुर राज्य सरकार को हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की अप्राकृतिक मृत्यु पर मृतक बन्दियों के आश्रितों/निकटस्थ परिजनों को मुआवजा भुगतान हेतु 'उत्तर प्रदेश बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति' बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

» मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के विभिन्न प्रस्तरों में निहित व्यवस्थाओं को संशोधित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

» मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में उप निबन्धक कार्यालय, मोहनलालगंज के भवन निर्माण हेतु ग्राम मऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ की नॉन-जेड0ए0 गाटा संख्या-1134 सम्पूर्ण रकबा 791 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या-1137 मि0 में 162 वर्गमीटर कुल दो किता रकबा 953 वर्गमीटर भूमि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को, सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियमावली 1987 यथासंशोधित नियमावली 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत, 90 वर्ष के पट्टे के माध्यम से कतिपय शर्तों के अधीन आवंटित/हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने ग्राम सभा बम्हरौली, परगना व तहसील मोंठ, जनपद झाँसी में गाटा संख्या-606 मि0 रकबा 9.777 हेक्टेयर भूमि में से पशुपालन विभाग की 05 एकड़ भूमि पर निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन सोनागिरी, शाखा झाँसी द्वारा गो-आश्रय स्थलों की स्थापना, पशु चिकित्सालय एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रश्नगत भूमि पर पशुपालन विभाग का स्वामित्व बना रहेगा। इस सम्बन्ध में पशुपालन विभाग एवं निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन के मध्य एम0ओ0यू0 किया जाएगा।

» मंत्रिपरिषद ने जनपद मुरादाबाद में नवीन जिला कारागार (2,000 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 38691.46 lakh रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

» मंत्रिपरिषद ने जनपद ललितपुर में नवीन जिला कारागार (552 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 22506.11 lakh रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

» मंत्रिपरिषद ने जनपद औरैया में नवीन जिला कारागार (1,056 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 26496.18 lakh रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

» मंत्रिपरिषद ने जनपद कानपुर नगर में नवीन जिला कारागार (2,030 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 38405.40 lakh रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

» मंत्रिपरिषद ने जनपद भदोही में नवीन जिला कारागार (574 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 20918.64 lakh रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

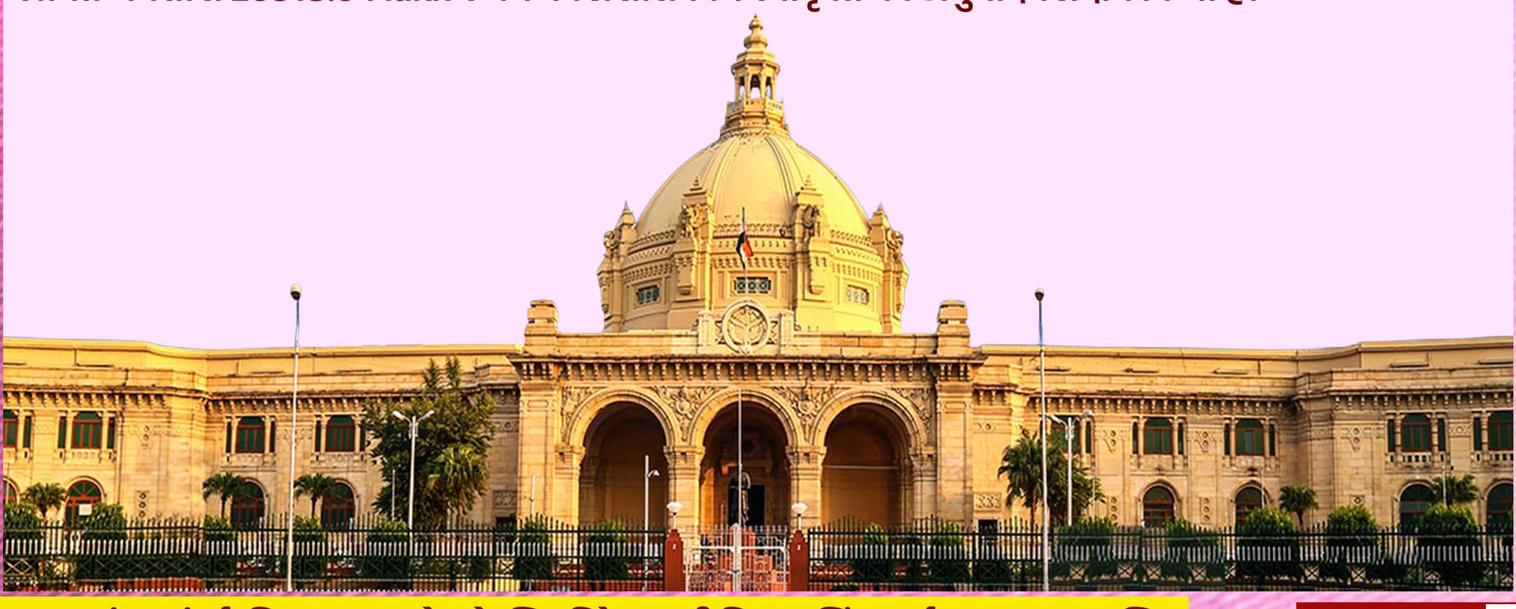

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित